



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2018/भाद्र 29, 1940

No. 662]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2018/BHADRA 29, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

सा.का. नि. 897 (अ).— चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 20 जून, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 575(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां 20 जून, 2018 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझाव पर विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची XI में,-

(क) पैरा 3 और 4 का लोप किया जाए;

(ख) पैरा 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखे जाए, अर्थात:-

“5. (1) विमान प्रचालक प्रमाणपत्र के लिए कोई आवेदन महानिदेशक को उस तारीख जिससे विमान परिवहन सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है, से पूर्व छह मास से अन्यून किया जा सकेगा जिसे महानिदेशक द्वारा ऐसी रीति और प्ररूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, वह आवेदन आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) आवेदक महानिदेशक को आवेदन करने से पूर्व वह ऐसी रीति और प्ररूप जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में आवेदन करके केन्द्रीय सरकार से अपने प्रस्तावित विमान परिवहन सेवा के लिए आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार आवेदक की सृद्ध वित्तीय स्थिति, उसकी प्रचालन योजना आवेदक के संगठन जिसके अन्तर्गत उसके निदेशक और कोई ऐसे अन्य विवरण जो नीति की दृष्टि से प्रस्तावित विमान परिवहन सेवा से संबंधित हो सकते हैं, की सुरक्षा के दृष्टिकोण जैसे तथ्यों को ध्यान से रखते हुए उप-पैरा (2) के अधीन प्राप्त आक्षेप न होने के प्रमाण पत्र के आवेदन पर विचार करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(5) आक्षेप न होने का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दो लाख रुपये की फीस देय होगी।

6. इस अनुसूची के अन्तर्गत विमान परिवहन सेवा के लिए निम्नलिखित प्रवर्ग में विमान प्रचालक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकेगा, अर्थात:---

(क) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (यात्री);

(ख) अनुसूचित कम्प्यूटर विमान परिवहन सेवा (यात्री); और

(ग) अनुसूचित विमान परिवहन सेवा (कार्गो)।

स्पष्टीकरण.— अनुसूचित कम्प्यूटर विमान परिवहन सेवा विमानपत्तनों और/या हेलीपैडों जिसे महानिदेशक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, के बीच प्रचालित की जा सकेगी।

7. इस अनुसूची के अधीन विमान प्रचालक प्रमाण पत्र के धारक द्वारा विमान की दशा में 5700 किलोग्राम से अन्यून अधिकतम प्रमाणित उड़ान भार वाले केवल मल्टी इंजन के विमान और हेलीकाप्टर की दशा में 3175 किलोग्राम हेलीकाप्टर का उपयोग किया जा सकेगा और विमान को उन अपेक्षाओं जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, की पूर्ति की जाएगी।

परन्तु यह तब जबकि अनुसूचित कम्प्यूटर विमान परिवहन सेवा (यात्री) का प्रचालक 5700 किलोग्राम से कम प्रमाणित उड़ान भार वाले विमान का उपयोग कर सकेगा परन्तु उस विमान का प्रमाणित उड़ान भार 40000 किलोग्राम से अधिक न हो

परन्तु यह और कि इस अनुसूचित कम्प्यूटर विमान परिवहन सेवा के अन्तर्गत 5700 किलोग्राम से कम सेवा के अन्तर्गत उड़ान भार वाले टर्बाइन पावर्ड सिंगल इंजन के विमान और 3175 किलोग्राम से कम अधिकतम प्रमाणित उड़ान भार वाले टर्बाइन पावर्ड सिंगल इंजन के हेलीकाप्टर का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, अर्थात:---

(i) प्रमाणित यात्रियों की सीटों की संख्या नौ से अधिक नहीं होगी;

(ii) विमान रात्रि में प्रचालन के लिए न्यूनतम उपस्करों और मौसमी दशाओं के उपकरणों से लैस होगा; और

(iii) हेलीकाप्टर की उड़ान केवल दृश्य उड़ान नियम के अधीन की जा सकेगी।”;

(ग) पैरा 8 में,

(i) उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाए, अर्थात:-

“(1) महानिदेशक विमान प्रचालक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पर यथा संभव शीघ्र विचार करेगा और इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि आवेदक उन विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, जो शर्तें उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन रहते हुए विमान प्रचालक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकेगा।”;

(ii) उप-पैरा (2) का लोप किया जाए;

(घ) पैरा 9, के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा को रखा जाए, अर्थात:-

“9. (1) विमान प्रचालक प्रमाणपत्र पाँच वर्ष से अनधिक अवधि जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विधिमान्य होगा और महानिदेशक द्वारा इसका नवीकरण एक बार पाँच वर्ष की अवधि के लिए इस बात का समाधानप्रद हो जाने पर कि आवेदक प्रमाणपत्र के अन्तर्गत सेवाओं का निष्पादन संतोषप्रद रूप से कर रहा है और सेवा जारी रखने के लिए सक्षम है, किया जा सकेगा।

(2) विमान प्रचालक प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बीस लाख रुपये और उसके नवीकरण के लिए दस लाख रुपये की फीस देय होगी:

परन्तु अनुसूचित कम्प्यूटर विमान परिवहन सेवा प्रचालित करने के लिए प्रचालक प्रमाणपत्र जारी करने की दशा में दस लाख रुपये और उसके नवीकरण के लिए पाँच लाख रुपये की फीस देय होगी।

(3) इस पैरा के अधीन देय फीस उस रीति जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, में देय होगी।”;

(ड.) पैरा 15 में, उप- पैरा (2) में,---

(i) खंड (घ) का लोप किया जाए;

(ii) खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएं, अर्थात:---

“(ड.) कि विमान परिवहन प्रमाण पत्र कपट से प्राप्त किया गया है;

(च) कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी या निगमित निकाय की सुरक्षा अनापत्ति वापस ले ली गई है या इंकार कर दी गई है।

[फा.सं.एवी.11012/2/2013-ए]

शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 को अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम संशोधन तारीख 30 अगस्त, 2018 की सां.का.नि. संख्या 821 (अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2018

G.S.R. 897(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 575(E), dated the 20th June, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to public;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 20th June, 2018;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Fourth Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule XI to the Aircraft Rules, 1937,—
 - (a) paragraphs 3 and 4 shall be omitted;
 - (b) for paragraphs 5, 6 and 7, the following paragraphs shall be substituted, namely: —

“5. (1) An application for Air Operator Certificate shall be made to the Director-General, not less than six months before the date on which it is proposed to commence the air transport services, in such form and manner as may be specified by the Director-General which shall be signed by the applicant or by a person duly authorised in that behalf by the applicant and the application.

(2) The applicant shall, before making the application to the Director-General, obtain a no objection certificate for his proposed air transport services from the Central Government by making an application to it in such form and manner as may be specified by the Director-General.

(3) The Central Government shall consider the application for no objection certificate received under subparagraph (2) taking into account the factors such as the financial soundness of the applicant, his operational plan, the clearance from security angle of the applicant organisation including its Directors, and any other factor that may have a bearing on the proposed air transport services from policy angle.

(4) The no objection certificate granted by the Central Government shall be valid for a period of three years from the date of issue.

- (5) A fee of two lakh rupees shall be payable for making the application for no objection certificate.

6. An Air Operator Certificate for air transport services under this Schedule may be granted in the following categories, namely: —

- (a) scheduled air transport services (passenger);
- (b) scheduled commuter air transport services (passenger); and
- (c) scheduled Air Transport Services (Cargo).

Explanation. — The scheduled commuter air transport services shall be operated between airports and/or helipads as may be specified by the Director-General from time to time.

7. Only multi-engine aircraft with maximum certified take off mass of not less than 5700 Kilograms in case of aeroplanes and 3175 Kilograms in case of helicopters shall be used for operations by the holder of the Air Operator Certificate under this Schedule and the aircraft shall meet the requirements as may be specified by the Director-General, from time to time:

Provided that the operator of scheduled commuter air transport services (passenger) may use aircraft with certified take off mass from below 5700 Kilograms but not exceeding 40000 Kilograms:

Provided further that turbine-powered single engine aeroplane having maximum certified take off mass below 5700 Kilograms and turbine-powered single engine helicopter having maximum certified take off mass below 3175

Kilograms may be used for operations under the scheduled commuter air transport services subject to the following conditions, namely: —

- (i) the number of certified passenger seats shall not exceed nine;
- (ii) the aeroplane shall be equipped with minimum equipment for operation at night and instrument meteorological conditions; and
- (iii) the helicopter shall be flown under day Visual Flight Rules (VFR) only.”;
- (c) in paragraph 8, —
 - (i) for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(1) The Director-General shall consider the application for the Air Operator Certificate as speedily as possible and upon being satisfied that the applicant meets the laid down requirements, shall grant the Air Operator Certificate subject to such conditions as may be specified therein.”;
 - (ii) sub-paragraph (2) shall be omitted;
- (d) for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely: —

“9. (1) The Air Operator Certificate shall be valid for a period not exceeding five years as may be specified therein and may be renewed by the Director-General for a period not exceeding five years at a time upon being satisfied that the applicant has been performing the services under the certificate satisfactorily and has the capability to continue the services.

(2) A fee of twenty lakh rupees shall be payable for the grant of an Air Operator Certificate and ten lakh rupees for renewal thereof:

Provided that in case of issue of an Air Operator Certificate to operate the scheduled commuter air transport service, the fee payable shall be ten lakh rupees and five lakh rupees for renewal thereof.

(3) The fees payable under this paragraph shall be paid in the manner as may be specified by the Director-General.”;

- (e) in paragraph 15, in sub-paragraph (2), —
 - (i) clause (d) shall be omitted;
 - (ii) for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely: —

“(e) that the air transport certificate was obtained by fraud; or

(f) that the security clearance of the company or the body corporate has been withdrawn or denied by the Central Government.”.

[F. No. AV.11012/2/2013-A]

SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 821(E), dated the 30th August, 2018.